

रेसपी फॉर अ लविबल प्लेनेट रपिर्ट: वशिव बैंक

प्रलिमिंस के लयि:

[कारबन सीकवेस्ट्रेशन/पृथककरण](#), [कृषि के कारण उत्सर्जन](#), [ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन](#), [UNFCCC](#), [कारबन क्रेडिट](#), [शुद्ध शून्य उत्सर्जन](#), पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित सामान्य मुद्दे, [जलवायु परिवर्तन](#), [कृषि के कारण ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन](#)

मेन्स के लयि:

कृषि के कारण उत्सर्जन, कृषि खाद्य उत्सर्जन का न्यूनीकरण

[स्रोत: वरल्ड बैंक](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [वशिव बैंक](#) ने एक "रेसपी फॉर अ लविबल प्लेनेट" नामक एक रपिर्ट जारी की, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि वर्ष 2030 तक कृषि खाद्य उत्सर्जन को आधा करने के साथ ही वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य लक्ष्य प्राप्त करने के लिये 260 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक निवेश आवश्यक है।

- रपिर्ट में स्पष्ट किया है कि यह आँकड़ा वर्तमान में कृषि सब्सिडी पर व्यय की जाने वाली राशिका दोगुना है।

रपिर्ट की मुख्य बातें क्या हैं?

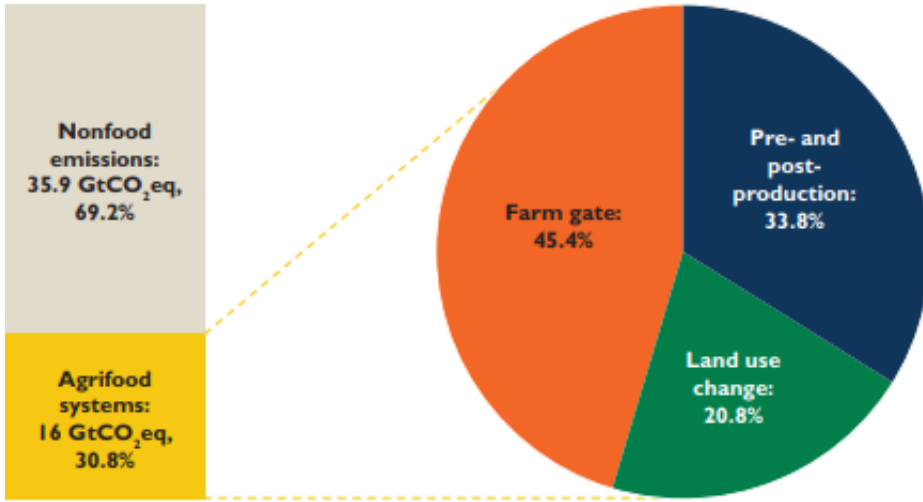
परिचय:

- "रेसपी फॉर अ लविबल प्लेनेट रपिर्ट" जलवायु परिवर्तन पर कृषि खाद्य प्रणाली के प्रभाव को कम करने हेतु एक वैश्विक रणनीतिक ढाँचा प्रदान करती है।
- यह रेखांकित करती है कि कैसे वशिव का खाद्य उत्पादन वैश्विक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए [ग्रीनहाउस गैस \(GHGs\) उत्सर्जन](#) को कम किया जा सकता है।

कृषि खाद्य प्रणाली सुधार की संभावनाएँ एवं लाभ:

- कमी की संभावना: वैश्विक कृषि खाद्य प्रणाली व्यवहार्य एवं सुलभ उपायों के माध्यम से वैश्विक रूप से GHG उत्सर्जन का लगभग एक तिहाई कम कर सकती है।
 - ये उपाय खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के साथ-साथ खाद्य प्रणाली पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम कर सकते हैं, जिससे [सुभेद्य समुदायों की सुरक्षा](#) प्राप्त होगी।

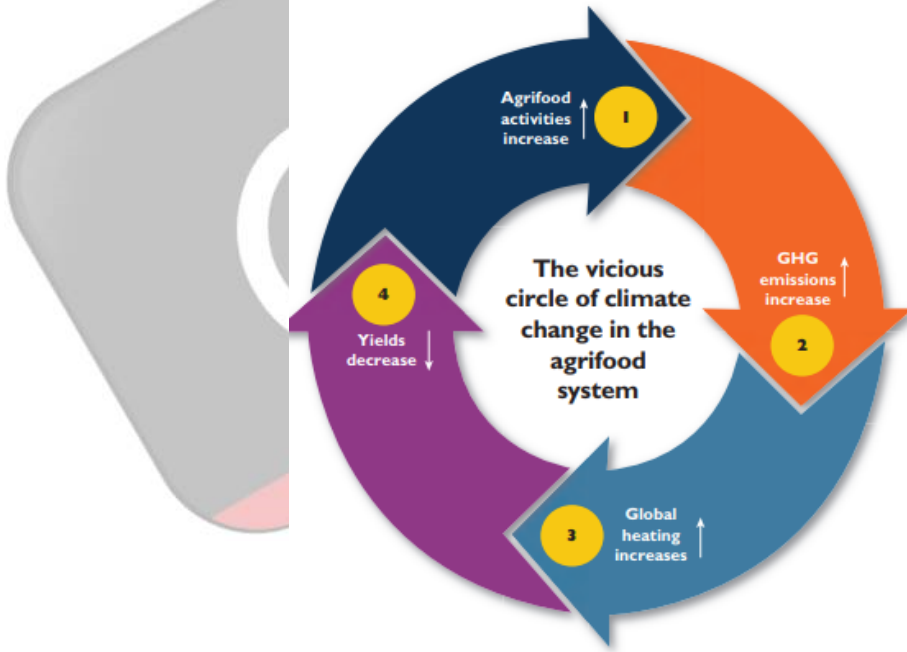
1.1 Greenhouse Gas Emissions from the Agrifood System Are Significantly Higher than Previously Thought



■ जलवायु परिवर्तन में कृषि खाद्य की भूमिका:

- **उत्सर्जन में योगदान:** कृषि खाद्य वैश्विक **GHG उत्सर्जन में लगभग एक तिहाई** का योगदान देते हैं, जो विश्व की कुल ऊष्मा एवं बजिली उत्सर्जनों से अधिक है।
- **उत्सर्जन के मुख्य योगदानकर्ता:** इनमें से लगभग तीन-चौथाई उत्सर्जन विकासशील देशों से उत्पन्न होता है, जिससे **क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार, लक्ष्य शमन कार्रवाई की आवश्यकता होती है।**
- **खाद्य मूल्य शृंखला से उत्सर्जन:** भूमि उपयोग परिवर्तन सहित संपूर्ण **खाद्य मूल्य शृंखला** से उत्सर्जन को संबोधित करना महत्वपूर्ण है क्योंकि आधे से अधिक उत्सर्जन कृषि क्षेत्र से परे होते हैं।

Positive Feedback Loops between Agrifood Activities and the Climate Have Created a Vicious Circle that Precludes Adaptation Alone as a Solution to the Crisis



रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं?

■ आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ:

- **अपर्युक्त क्षमता:** कृषि खाद्य क्षेत्र जलवायु कार्रवाई के लिये महत्वपूर्ण, लागत प्रभावी अवसर प्रदान करती है, जिसमें उन्नत भूमि प्रबंधन के माध्यम से वातावरण से कार्बन प्रग्रहण भी शामिल है।
- **निवेश पर रटिर्न:** वर्ष 2030 तक कृषि खाद्य उत्सर्जन को आधा करने के लिये आवश्यक वित्तीय परियोजना से पर्याप्त रटिर्न प्राप्त

होगा, जो स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर लाभकारी प्रभाव के साथ लागत से कहीं अधिक होगा।

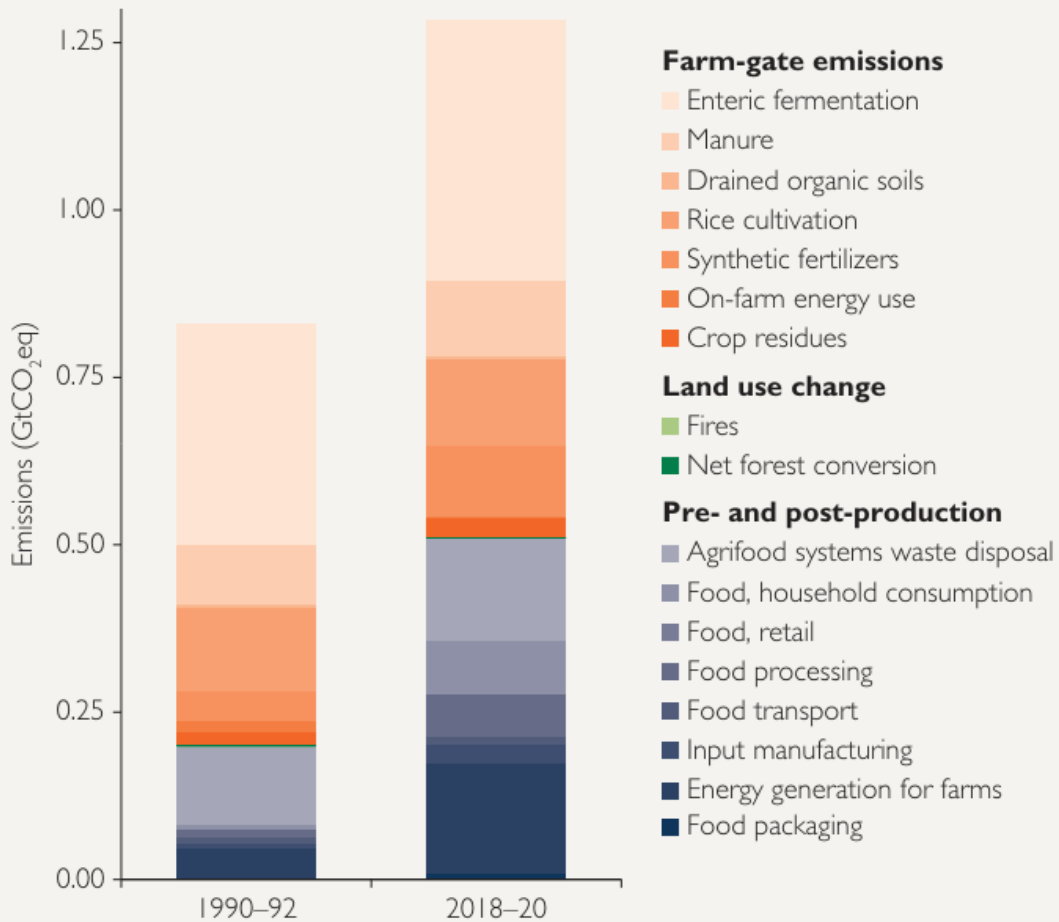
■ देशों और विश्व स्तर पर कार्रवाई के अवसर:

- उच्च आय वाले देशों की भूमिका: इन देशों को अपनी कृषि खाद्य ऊर्जा माँगों को कम करना चाहिये, वित्तपोषण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से नमिन आय वाले देशों का समर्थन करना चाहिये तथा उच्च उत्सर्जन वाले खाद्य पदार्थों से दूर उपभोक्ता आहार को संशोधित करना चाहिये।
- मध्य-आय वाले देशों की भूमिका: ये देश बेहतर भूमि उपयोग प्रबंधन और कृषि पद्धतियों के माध्यम से महत्वपूर्ण उत्सर्जन में कमी ला सकते हैं।
- नमिन आय वाले देशों की भूमिका: उच्च उत्सर्जन वाले बुनियादी ढाँचे के बोझ के बिना [सतत विकास](#) पर ध्यान केंद्रित करना, उत्पादकता और लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिये कृषि वानिकी जैसी रणनीतियों का भी लाभ प्राप्त होना चाहिये।

■ देश और वैश्विक स्तर पर कार्रवाई:

- नविश और नीति पहल: कृषि खाद्य श्रमण में नविश को बढ़ाना, सब्सिडी का पुनर्वितरण करना तथा न्यून उत्सर्जन प्रौद्योगिकियों के उपयोग की नीतियों को लागू करना।
- नवाचार और संस्थागत समर्थन: उत्सर्जन डेटा के लिये डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना तथा कृषि खाद्य प्रणाली को बदलने के लिये नई प्रौद्योगिकियों में नविश करना, जिससे उचित परिवर्तन के लिये समावेशी हतिधारक भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

FIGURE B3.1.1 India's Agrifood System Emissions, 1990–92 and 2018–20



Source: Data from World Bank and FAOSTAT 2023c.
Note: GtCO₂eq = gigatons of carbon dioxide equivalent.

रिपोर्ट में भारत से संबंधित मुख्य बडि क्या हैं?

■ वैश्विक कृषि खाद्य उत्सर्जन में भारत का योगदान:

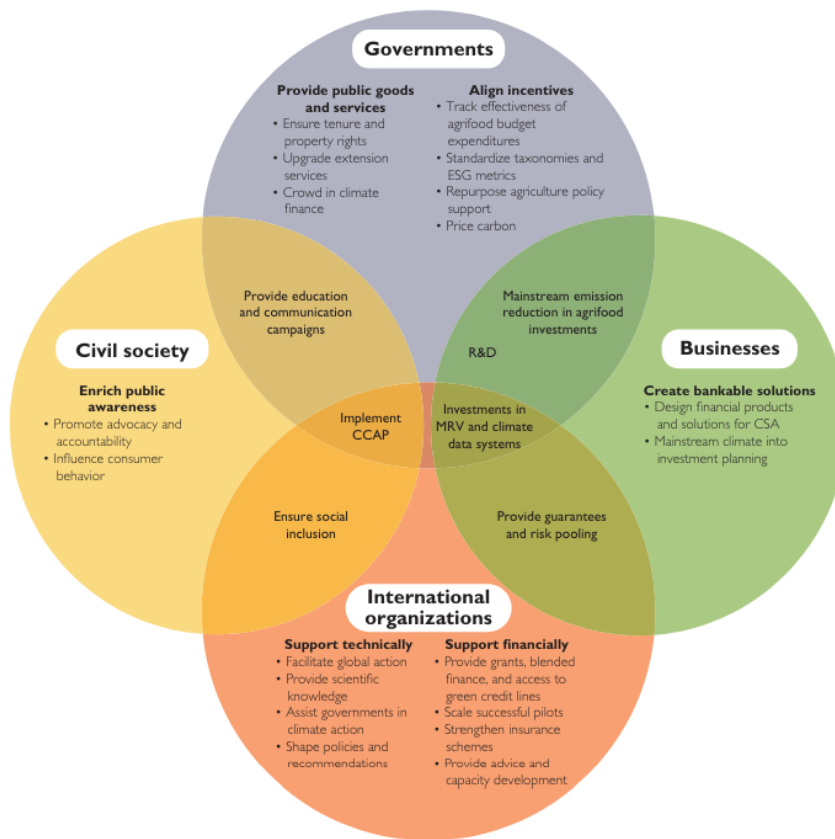
- रिपोर्ट में भारत को चीन और ब्राज़ील के साथ कुल वार्षिक कृषि खाद्य प्रणाली उत्सर्जन के मामले में शीर्ष 3 देशों में से एक के रूप में पहचान मल्लि है।

■ भारत में लागत प्रभावी श्रमण क्षमता:

- रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत जैसे देशों में कृषि में लगभग 80% तकनीकी श्रमण क्षमता अकेले लागत-बचत उपायों को अपनाकर प्राप्त की जा सकती है।
 - यह भारत के लिये उत्सर्जन को कम करने के साथ-साथ कृषि उत्पादकता एवं आय में सुधार करने का एक बड़ा अवसर है।

- **भारत के लिये प्रमुख शमन वकिलप:**
 - भारत के लिये प्रमुख शमन वकिलपों में **बेहतर पशुधन आहार (हरति धारा, एक एंटी-मथिनोजेनकि चारा)** और प्रजनन, उर्वरक प्रबंधन तथा जल सघन फसलों में बेहतर जल प्रबंधन शामिल हैं।
 - भारत के कृषि क्षेत्र के लिये **सीमांत उपशमन लागत वक्कर** से पता चलता है कि ये कुछ सबसे अधिक लागत प्रभावी उपाय हैं जिन्हें भारत वर्ष 2030 तक **कृषि खाद्य उत्सर्जन में काफी हद तक कमी करने** के लिये अपना सकता है।
 - भारत को कृषि उत्पादन से **मीथेन उत्सर्जन** पर अंकुश लगाने की जरूरत है।
 - **धीरे-धीरे सचिाई करने जैसी पद्धतियों** को अपनाने तथा कम मीथेन उत्सर्जति करने वाली फसल कसिमें को वृद्धि करने से उत्सर्जन शमन के अवसर मिलते हैं।
 - भारत में भोजन हानि और बर्बादी की दर उच्च है। **खाद्य अपशषिट सूचकांक रषिर्त 2021** के अनुसार, भारतीय परवार **प्रतवियक्ती प्रतविरष 50 कलोग्राम** खाद्य अपशषिट उत्पन्न करते हैं।
 - भारत में खाद्य हानि और बर्बादी को कम करने के साथ-साथ अन्य उच्च प्रभाव वाले अवसरों से आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की आवश्यकता:** भारत को अपनी कृषि-खाद्य शमन क्षमता के लिये **अंतर्राष्ट्रीय वत्तीय और तकनीकी सहायता** की आवश्यकता होगी।

FIGURE 0.11 Governments, Businesses, Civil Society Groups, and International Organizations All Have Roles to Play in Scaling Climate Action



आगे की राह

- **नविश:** सरकारों और व्यवसायों को मशरति वत्ति, कॉर्पोरेट जवाबदेही तथा वसितारति कार्बन बाजारों के माध्यम से कृषि खाद्य **मैजिी जलवायु नविश को जोखमि से मुक्त** करना चाहिये।
- **प्रोत्साहन:** नीति निर्माताओं को **कृषि खाद्य प्रणाली परविरतन** जैसे हानिकारक सब्सिडी का पुनः उपयोग करना और नीति सुसंगतता सुनिश्चति करने में तेज़ी लाने के लिये उपायों को लागू करना चाहिये।
- **जानकारी:** **डजिटल प्रोद्योगकियों का उपयोग करके GHG नगिरानी, रषिर्तगि और सत्यापन (MRV) प्रणालियों में सुधार करने से क्षेत्र के लिये जलवायु वत्ति को उपलब्ध कराने में सहायता मलि सकती है।**
- **नवाचार:** लागत प्रभावी शमन प्रोद्योगकियों का वसितार और अनुसंधान एवं वकिस नविश में वृद्धि से कृषि खाद्य प्रणालियों के भवषिय में परविरतन को बढ़ावा मलि सकता है।
- **संस्थाएँ:** अंतर्राष्ट्रीय ढाँचे, राष्ट्रीय नीतियों और उपराष्ट्रीय पहलों को समन्वति तरीके से कृषि खाद्य शमन के अवसरों को सुवधाजनक बनाना चाहिये।
- **समावेशन:** परविरतन को हतिधारक जुड़ाव, लाभ साझाकरण और सामाजिक सशक्तीकरण के माध्यम से छोटे कसिनों जैसे कमजोर समूहों की रक्षा

करके एक उद्यति परविरतन सुनश्चिति करना चाहयि ।



संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियाँ- UNSAs

Part V
(IMF,
World Bank
तथा
UNESCO)

UNSAs संयुक्त राष्ट्र के साथ कार्य करने वाले 15 स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

- स्थापना - 1944 (1930 के दशक की महामंदी के बाद संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन)
- मुख्यालय - वाशिंगटन DC, USA
- कार्य -
 - » वैश्विक वित्तीय सहायता
 - » अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना
 - » विकासशील देशों के लिये वित्त पोषण
 - » विनिमय दर स्थिरता को बढ़ावा देना
- सदस्य - 190 (भारत इसका संस्थापक सदस्य)

भारत के वित्त मंत्री IMF के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में पदेन गवर्नर हैं

- विशेष आहरण अधिकार (SDR) -
 - » IMF की आरंभिक आरक्षित परिसंपत्तियाँ अपने सदस्य देशों के आधिकारिक भंडार को परिशिष्ट करने के लिये हैं (न कि मुद्राओं को)
- SDR बास्केट में मुद्राएँ - \$ (डॉलर), € (यूरो), £ (पाउंड), ¥ (येन) और CN¥ (रेंमिन्बी)
- IMF कोटा -
 - » विश्व अर्थव्यवस्था में एक सदस्य देश की सापेक्ष स्थिति को दर्शाता है (भारत - 2.75%)
 - » SDR में नामांकित
- प्रमुख प्रकाशन -
 - » वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक
 - » वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट
 - » फिस्कल मॉनिटर
 - » एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट

विश्व बैंक समूह (WBG)

- स्थापना- IMF के समान
- मुख्यालय- वाशिंगटन DC, USA

WBG के 5 संस्थान (स्था.)

- अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (IBRD) अर्थात् विश्व बैंक (1944)
- अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) (1956)
- अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA) (1960)
- निवेश विवादों के निपटारे के लिये अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (ICSID) (1966)
- बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (MIGA) (1988)

IMF की सदस्यता IBRD की सदस्यता के लिये एक पूर्व शर्त है

कार्य

- ऋण, लोन एवं अनुदान प्रदान करना
- कंपनियों या सरकारों को निवेश, सलाह एवं परिसंपत्ति प्रबंधन
- कम आय वाले देशों को कम ब्याज दर पर या ब्याज रहित ऋण प्रदान करना
- निवेश-विवादों का समाधान करना
- राजनीतिक जोखिमों से ऋणकर्ताओं या निवेशकों को संरक्षण

- सदस्य - 189 (भारत IBRD, IFC और IDA के संस्थापक सदस्य हैं)

भारत ICSID का सदस्य नहीं है; भारत का मानना है कि यह विकसित देशों के प्रति झुकाव रखता है

- WBG के दोहरे लक्ष्य -
 - » वर्ष 2030 तक अत्यंत निर्धनता को समाप्त करना
 - » सभी देशों में सबसे निर्धन 40% आबादी की समृद्धि को बढ़ावा

- प्रमुख प्रकाशन -
 - » मानव पूंजी सूचकांक
 - » विश्व विकास रिपोर्ट

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (UNESCO)

- स्थापना- 1945 {CAME द्वारा प्रस्तावित (कॉन्फ्रेंस ऑफ अलाइड मिनिस्टर्स ऑफ एजुकेशन)}
- मुख्यालय - पेरिस, फ्रांस
- विशेषज्ञता के क्षेत्र -
 - » शैक्षिक विकास (पूर्व-विद्यालय से उच्च शिक्षा तक)
 - » धरोहर का संरक्षण, रचनात्मकता को बढ़ावा
 - » एक सतत् भविष्य के लिये विज्ञान
- UNESCO की वैश्विक प्राथमिकताएँ -
 - » अफ्रीका
 - » लैंगिक समानता
- सदस्य - 193 (भारत सहित) + 11 सहयोगी

USA UNESCO का सदस्य नहीं है

- महत्वपूर्ण पहलें -
 - » विश्व धरोहर सम्मेलन और विश्व धरोहर स्थलों (WHS) की सूची (भारत में 40 WHS हैं)
 - » मैन एंड द बायोस्फीयर (MAB) कार्यक्रम
 - » इंटरनेशनल जियोसाइंस एंड ग्लोबल जियोपार्क्स प्रोग्राम (IGPP)
 - » अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर (ICH) पर सम्मेलन

भारत ने ICH समिति के सदस्य के रूप में दो बार सेवा की है

- महत्वपूर्ण रिपोर्टें -
 - » UNESCO विज्ञान रिपोर्ट
 - » वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट
 - » भारत के लिये UNESCO स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट: चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी

दृष्टि मैनस प्रश्न:

वर्श्व स्तर पर शीर्ष उत्सर्जकों में से एक होने की स्थिति को देखते हुए, भारत कृषि खाद्य प्रणाली से अपने उत्सर्जन को कैसे कम कर सकता है? स्थिरता और खाद्य सुरक्षा के लिये संभावित रणनीतियों तथा उनके नहितार्थों पर चर्चा कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. कभी-कभी सामाचारों में आने वाली 'गाडगलि समति रिपिरट' और 'कस्तूरीरंगन समति रिपिरट' संबंधति हैं: (2016)

- संवैधानकि सुधारों से
- गंगा कार्य-योजना से
- नदियों को जोड़ने से
- पश्चिमी घाटों के संरक्षण से

उत्तर: (d)

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजिये- (2021)

- 'शहर का अधिकार' एक सम्मत मानव अधिकार है तथा इस संबंध में, संयुक्त राष्ट्र हैबटिट (यू. एन. हैबटिट) प्रत्येक देश द्वारा की गई प्रतबिद्धताओं को मॉनटिर करता है।
- 'शहर का अधिकार' शहर के प्रत्येक नवासी को शहर में सार्वजनकि स्थानों को वापस लेने (रीक्लेम) एवं सार्वजनकि सहभागति का अधिकार देता है।
- 'शहर का अधिकार' का आशय यह है किराज्य, शहर की अनधकित बस्तियों को कसि भी लोक सेवा अथवा सुवधि से वंचति नहीं कर सकता।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- केवल 1
- केवल 3
- 1 और 2
- 2 और 3

उत्तर: (c)